Non-Disclosure of Rate of Interest as an Unfair Trade Practice

1722. SHRI PARMESHWAR KUMAR AGARWALLA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether the attention of Government has been invited to a news-item in Economic Times of 13th July, 1995 captioned "Interest rates deceptive appearances";

(b) if so, whether the non-disclosure of effective rate of interest would be considered as Unfair/Restrictive Trade Practice within the provisions of the MRTP Act of any other provisions of law; and

(c) what action Government propose to take to curb such a practice being followed by some of the foreign banks, housing and consumer durable finance institutions/companies both public and private and other institutions?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW, JUSTICE & COMPANY AFFAIRS (SHRI H.R. BHARDWAJ): (a) Yes, Sir.

(b) and (c) The said news item has discussed the issue in general without naming any particular company indulging in such dealings. If any specific case of this nature, which *prima facie* appears to be unfair/restrictive trade practice within the provisions of MRTP Act, comes to the notice MRTP Commission it is empowered to take required necessary action.

In past the MRTP Commission has initiated action wherever such specific cases were brought to its notice. It has instituted Unfair Trade Practice Enquiries against M/s. Apple Leasing and Industries Limited, and M/s 20th Century Financing Corporation Limited for making claims in respect of interest rate for car financing.

Growth rate of Industry

1723. SHRI G.G. SWELL:
SHRI CHIMANBHAI MEHTA:

Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) the growth rate of Industry from April, 1994 till date;

(b) what is the projection of the industrial growth rate in the current and next year;

(c) how much of the proposed investment amounting to Rs. 1,07,000 crores in 1994 and Rs. 77,000 crores in 1993 has materialised;

(d) what is the total foreign investment proposed and already made since 1991;

(e) whether it is a fact that industry requires cheaper finance through removal of the restriction for corporate investment and deposits; and

(f) if so, what are the hurdles?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRIMATI KRISHNA SAHI): (a) As per the latest Quick estimates released by CSO, the overall growth of industrial production during 1994-95 (April, 1994 to March 1995) has been 8.4 percent.

(b) Targets for the overall industrial growth are not fixed on a year to year basis.

(c) During the years 1993 and 1994, a total of 4456 and 4664 IEMs with proposed investment of Rs. 63,976 and Rs. 88,771 crores, respectively, were filed. Actual implementation of the proposals depend on various factors such as availability of finance, power and other infrastructural facilities.

(d) The total amount of foreign equity involved in the proposals approved during August 1991 to March, 1995 is Rs. 24,310 crores. The actual direct foreign equity inflows during 1991-92 to 1994-95 have been Rs. 5,216 crores.

(e) and (f) The steps taken to enhance the competitive environment and make credit available at reasonable terms include, interalia, reduction in the banks' statutory liquidity ratio (SLR) and cash reserve ratio (CRR) and abolition of minimum lending rates for amounts over Rs. 2.0 lakhs. The rates of advances for smaller amounts have been reduced.

आयकर अधिकरणों द्वारा हिन्दी में दिया गया निर्णय

1724. **श्री राघवजी:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान हिन्दी भाषी राज्यों में स्थापित आयकर अधिकरणों द्वारा कितने प्रतिशत निर्णय हिन्दी में दिये गये है;

(ख) क्या यह सच है कि आम तौर से आयकर अधिकरण "अंग्रेजी" भाषा में अपना निर्णय देते है, और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) "हिन्दी भाषी" राज्यों में स्थापित अधिकरणों द्वारा हिन्दी के अधिकतम प्रयोग को सुनिश्चित करने के लिए क्या-क्या कदम उठाये गये हैं और यदि कोई कदम नहीं उठाये गये है, तो उसके क्या कारण हैं?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज): (क) हिन्दी भाषी राज्यों में स्थित आय-कर अपील अधिकरण की न्यायपीठों द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान कोई मूल निर्णय हिन्दी में नहीं दिए गए हैं। तथापि, हिन्दी भाषी राज्यों में, अंग्रेजी में दिए गए आदेशों का हिन्दी में अनुवाद किया जाता है और इन आदेशों को आय-कर अपील अधिकरण के मासिक बुलेटिन में प्रकाशित किया जाता है।

(ख) जी हां। अधिकरण की विभिन्न न्यायपीठों में तैनात किए गए सदस्य आवश्यक रूप से हिन्दी भाषी नहीं होते हैं। अधिकरण की प्रत्येक न्यायपीठ में एक लेखा सदस्य और एक न्यायिक सदस्य होता है। यदि न्यायपीठ का गठन करने वाले सदस्यों में एक सदस्य को हिन्दी का ज्ञान नहीं है तो उस न्यायपीठ के लिए, हिन्दी में दिए गए तर्कों को ठीक-ठाक समझने या हिन्दी में आदेश देने की कोई गुंजाइश नहीं है।

(ग) हिन्दी भाषी राज्यों में स्थित अधिकरण की न्यायपीठों द्वारा हिन्दी का अधिकतम प्रयोग किए जाने को सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:—

(i) गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान और बिहार राज्यों में स्थित अधिकरण की न्यायपीठों के समक्ष हिन्दी में तैयार किए गए दस्तावेज फाइल किए जा सकते हैं। यह उपबंधित करने के लिए भी आदेश जारी कर दिए गए हैं कि इन राज्यों में स्थित अधिकरण की न्यायपीठें स्वविवेकानुसार, अपने समक्ष कार्यवाहियों में हिन्दी के प्रयोग को अनुज्ञात कर सकेंगी और हिन्दी में आदेश पारित कर सकेंगी।

(ii) राजभाषा अधिनियम, 1963 राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजन के लिए प्रयोग) नियम, 1976 और राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम के अन्तर्विष्ट उपबंधों को हिन्दी भाषी राज्यों में स्थित अधिकरण की न्यायपीठों में लागू किया जा रहा है। सभी हिन्दी भाषी राज्यों में सुनवाई, स्थगन, आदि के संबंध में सूचनाएं हिन्दी में ही जारी की जाती हैं। हिन्दी के प्रयोग में हुई प्रगति का इन न्यायपीठों की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों में नियमित रूप से पुनर्विलोकन किया जाता है।

MOU signed between India and Morocco

1725. SHRI GHUFRAN AZAM: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government have entered into an understanding with the Government of Morocco for the development and providing Indian expertise on the different energy sector;

(b) whether Government had deputed Indian experts during the last one year to the Government of Marocco in consultation with the Department of Non-Conventional Energy Sources;

(c) whether any report has been submitted by the Indian experts; and

(d) if so, the details thereof?